

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 30 जनवरी 2025 गुरुवार

सम्पादकीय

महाकुंभ में मौतें, भगदड़ और तंत्र

मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ में 30 लोगों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की घटना ने निविघ्न कुंभ के आयोजन के दावे को धराशायी कर दिया है। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि किन्हीं मौतें हुईं, कितने घायल हैं। कुंभ में भगदड़ और मौतों की घटना कोई नया नहीं है। अच्छा हो कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे। पहले से ही यह आशंका जातीय या रही थी कि जिस प्रकार से प्रयागराज में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसमें कोई अनहोनी हो सकती है। महाकुंभ में पहले से ही विविध जनों को विशेष असर देने को लेकर प्रबंधन की आलोचना हो रही थी। अब जरूरत है कि सरकार घेतें और भाविय में और कोई अनहोनी न होने पाये। मृतकों के शव उनके परिजनों को देने के साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी जाय।

संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू हुआ महाकुंभ मेला ठीकठाक संचालित हो रहा था, लेकिन 28 जनवरी की रात भगदड़ फैल गई। घटना में कुछ श्रद्धालुओं के स्वर्गसाथी होने जबकि कुछ के घायल होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के साथ-साथ संतों-महंतों से भी अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रद्धालु संगम नोज पर ही स्नान करने की जित न पालें ताकि किसी तरह की दुर्घटना की आशंका पैदा नहीं हो। उत्तर, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने मेले में कुलुबंन का आरोप लगाया है। वहीं, लोकभार में विश्वास के नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बर्दाश्तजामाई को ही भगदड़ के लिए जिम्मेदारी ठहराया है। आइए जानते हैं कि महाकुंभ में मेले को व्यवस्थित रखने के लिए किस तरह का प्रबंधन किया गया है।

सबसे ज्यादा भीड़ 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होने की बात सबको पता थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि करीब 6 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ मेले में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने 10 करोड़ लोगों के प्रबंधन की व्यवस्था की है। अनुमान के मुताबिक, मौनी अमावस्या के दिन देश-दुनिया के कोने-कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। भारी भीड़ के कारण बुधवार की रात ही स्नान होने लगा। प्रयागराज में जिस जगह 'गंगा'-यमुना और विष्णु सस्वती नदी का संगम हुआ है, वहीं साधु-संत स्नान करते हैं। इस वजह से इसे प्रयागराज का पवित्रतम घाट माना जाता है। इसी घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और रात करीब डेढ़ बजे संगम नोज पर भगदड़ मच गई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि श्रद्धालु जिस घाट पर जगह मिले, उधर ही जाएं ना कि किसी एक घाट पर ही स्नान करने की होश में चूट जाए।

प्रयागराज महाकुंभ के लिए करीब हफ्तेदर में मेला क्षेत्र बनाया गया है। मौनी अमावस्या को भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाकर ही नदी किनारों पर जगह बढ़ाई गई थी ताकि हर घंटे दो लाख श्रद्धालु स्नान कर सकें। पहले यह क्षमता 50 हजार श्रद्धालुओं की ही थी। भीड़ इतनी ज्यादा आई कि सुबह तक ही तनी करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान कर लिया।उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला पुलिस को राज्य का 76वा जिला ही घोषित कर दिया। करीब 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसे महाकुंभ नगरी को 25 सेक्टर में बांटा गया है। इनमें 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई हैं और सुरक्षा बलों के करीब 40 हजार जवान तैनात हैं। हर थाने में साइटवर डेस्क हैं। इतना ही नहीं, दो साइटवर थाने भी अलग से बनाए गए हैं। महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बताया था, 'सिविल पुलिस, पीएसपी, एनएसपी, एस्टीएफ, होमगार्ड, डिफेंस और एनजीओ को मिलाकर मेले में 60 हजार से ज्यादा लोग सुरक्षा व्यवस्था संचालेंगे।' महाकुंभ सात स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है जिनमें एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती है। इसके बावजूद सुरक्षा तंत्र विफल हो गया।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेले में एआई युक्त कैमरे लगे हैं जो लोगों की गिनती करते हैं। अगर किसी इलाके में 2 हजार लोगों के छह होने की जगह है तो 1,800 लोग होने ही संबंधित अफसर को जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा, 100 फीस रिकनिशन कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस रिजॉर्ड में पहले से संदिग्धों को आसानी से चिह्नित किया जा सकेगा। 2,700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं, ड्रोन से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी हो रही है। पानी के अंदर की सुरक्षा के लिए पहली बार नदी के अंदर 8 किलोमीटर तक डीप बैरिकेडिंग भी है। मेले में अगर कोई खो जाए तो मदद के लिए हॉटलैक 10 खोया-पाया करें हैं। इतनी व्यवस्था के बाद घटना का घटित होना चिन्ताजनक है।

मेला क्षेत्र में लगभग 1.50 लाख टेंट, तीन हजार रसोई, 145 ला शेचालन, 300 मॉबाइल शौचालय और 100 से अधिक पार्किंग स्थल बने हैं। इनके अलावा, प्रयागराज के बुनियादी ढांचे के विकास और सौंदर्यीकरण में लगभग 7,000 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। 14 रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज के साथ-साथ 61 सड़कें बनाई गई हैं। इनके अलावा, 40 चौराहा का सौंदर्यीकरण और रेलवे लाइन विस्तार का निर्माण हुआ है। वहीं, 30 पार्किंग प्लट बने। इनमें 15 प्लट सड़क के बिल्कुल करीब बनाए गए हैं। 41 बाटो पर करीब 10 हजार जॉइंटिंग रूम हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी गंगा और 300 से अधिक गोताखोरा तैनात हैं। इतनी व्यापक व्यवस्था के बावजूद भगदड़ मची तो पूरी ही नहीं, केंद्र सरकार की अलर्ट मोड में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चार बार बात की। दूसरी तरफ, विविध कमियां गिनाने में लगे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यह भगदड़ अव्यवस्था के कारण मची। वहीं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दावा किया कि महाकुंभ में इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बर्दाश्तजामाई और आम श्रद्धालुओं की जगह बीआईपीएम पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है।[तात और सुरक्षित महाकुंभ मेले के आयोजन पर करीब 7,500 करोड़ रुपया खर्च होने की बात की जा रही है। ऐसे में दावों का सच सामने आ गया। अच्छा हो कि जिम्मेदारों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाय।

बजट पर टिकी निगाहें और मध्यम वर्ग

—डॉ. जयंतीलाल भंडारी—

इन दिनों पूरे देश के साथ-साथ मध्यम वर्ग की निगाहें वित्तमंत्री द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 की ओर लगी हुई हैं। दरअसल, देश के विकास का इंजन कहे जाने वाले मध्यम वर्ग की मुश्किलों में धन की कमी के कारण उनके निजी उपभोग पर होने वाले खर्च में गिरावट से विकास दर प्रभावित हो रही है। उम्मीद है कि वित्तमंत्री आगामी बजट में टेक्स में कटौती और वित्तीय प्रोत्साहनों से आयकरदाता और मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाएंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्तमंत्री नए टेक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की कमाई को टेक्स फ्री कर सकती है। इससे मध्यम वर्ग के हथ में जो अतिरिक्त धनराशि बचेगी, उससे खपत बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी।

वस्तुतः मध्यम वर्ग के खर्च और निजी उपभोग का देश की विकास दर की रफ्तार से सीधा संबंध है। कोरोना-19 के बाद से मध्यम वर्ग के पास अपने उपभोग खर्च के बाद निवेश के लिए खर्च में लगातार कमी आ रही है। मध्यम वर्ग की जीवधारियों को बनाए रखने की लागतों में अत्यधिक तेज वृद्धि ने इस वर्ग की वित्तीय मजबूती कम की है। बचती हुई, खुदरा महंगाई ने भी मध्यम वर्ग के परिवारों पर वित्तीय दबाव को बढ़ा दिया है। पिछले वर्ष 2024 में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित मालक से



अधिक रही है। स्थिति यह है कि निजी उपभोग में कमी ने निजी पूंजीगत व्यय के चक्र की रफ्तार घटा दी है। कोविड-19 के बाद मध्यम वर्ग की कमाई की रफ्तार में कम आई है। साथ ही बचती वित्तीय देनदारी और कर्ज की किस्त अदायगी का बोझ बढ़ने से मध्यम वर्ग वित्तित है।

नि:संदेह, सरकार ने विगत वर्ष में जहां गरीब लोगों के लिए दर सारी राहतों का ऐलान किया, वहीं कोपरेट जगत पर भी सरकार ने 6

यान दिया। लेकिन सबसे अधिक टेक्स देने वाला मध्यम वर्ग पीछे छूट गया। पिछले विभिन्न बजटों में मध्यम वर्ग की वित्ताओं पर विशेष 6 यान नहीं दिया गया है। इस वर्ग पर लुआए गए कर की तुलना में इस वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं के जरिए बहुत कम रिटर्न मिला है, ऐसे में यह अपेक्षा की गई है कि आगामी बजट सरकार के लिए लक्षित कर में सुधार को आगे बढ़ाने, जरूरी उपभोग मांग को बढ़ाने और मध्यम वर्ग को सीधे लाभ पहुंचाने वाली सेवाओं को

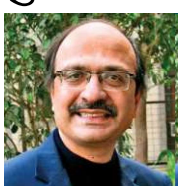
उल्लेखनीय है कि पिछले 10 वर्षों में लगातार आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और अंतर्गत लाभ भार 80री के तहत घट्ट बढ़ाई जा सकती है। नए बजट में अंशिल से डिसेंबर, 2024 तक

आयकर सहित प्रत्यक्ष कर संग्रहण करीब 16 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 16 फीसदी से भी ज्यादा है। इस परिदृश्य में आईटीएस की रिपोर्ट के तहत 75,000 रुपये की कटौती का लाभ मिलता है।

वहीं दूसरी ओर अमी आयकर के कर दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले, महंगी आरामदायक व विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले तथा पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से भी बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। स्थिति यह है कि वर्ष 2023-24 में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों ने से सिर्फ 8.09 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए। इनमें से भी 4.90 करोड़ लोगों ने शून्य कर योग्य आय की सूचना दी। सिर्फ 3.19 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है। ऐसे में देश के सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का योगदान बहुत कम बना हुआ है।

वित्तमंत्री आकर सुचारों के तहत वर्ष 2025-26 के बजट संरचना में गया आयकर कानून में संशोधन कर सकते हैं। इसका महकदम मजबूत इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमान्य, स्पष्ट और समझने योग्य बनाया है। इसके तहत आयकरवर्ग और अवस्थिति प्राक्कानों को हटाय जाया है। कर विवादों को कम किया जाएगा। टेक्सपेयर्स के लिए अनुमान का आसान बनाया जाएगा।—लेखक अध्यापक हैं।

दुनिया की दुखती रग पर ट्रंप की चोट



—दिनेश सी. शर्मा—

अमेरिकी राष्ट्रपति का ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जिन कार्यकारी आदेशों पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए उनमें एक है विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका का हटना। आदेश में दलील दी गई है कि यह निर्णय चीन के वुहान से शुरू हुई कोविड महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों को ठीक से न संभाल पाना, फोरी तौर पर जिन सुधारों की जरूरत थी उन्हें करने में विफलता और संगठन के सदस्य देशों के अनुचित राजनीतिक प्रभाव से खुद को मुक्त रखने में इसकी 'अक्षमता' के बाद लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अमेरिका जिन जैसे देशों की तुलना में विश्व स्वास्थ्य संगठन को 'कहीं अधिक' सहायता दे रहा है, दुर्भाग्यवश चीन की आयुर्वि



अमेरिकी राष्ट्रपति का ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जिन कार्यकारी आदेशों पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए उनमें एक है विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका का हटना। आदेश में दलील दी गई है कि यह निर्णय चीन के वुहान से शुरू हुई कोविड महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों को ठीक से न संभाल पाना, फोरी तौर पर जिन सुधारों की जरूरत थी उन्हें करने में विफलता और संगठन के सदस्य देशों के अनुचित राजनीतिक प्रभाव से खुद को मुक्त रख पाने में इसकी 'अक्षमता' के बाद लिया गया है।

डब्ल्यूएचओ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, स्वास्थ्य और बीमारियों के महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के संकल्प में एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के रूप में किया गया था। इसे वैज्ञानिकों, चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य नीति निर्माताओं के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व युक्त एक तकनीकी एजेंसी के रूप में एक तंत्र करने के लिए अभिकल्पित किया गया था। इसके मुख्य कार्यों में एक है नए पदों पर रहे सक्षमताओं पर निगरानी और सूचना साझा करना। दशकों से इस एजेंसी के काम ने चेचक, रॉस, पीला बुखार, कुष्ठ और और पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन और नियंत्रण में मदद की है। पूरा एडस नकार एक नई एजेंसी के माध्यम से इसकी एचआईवी/एड्स पर की वैश्विक कार्रवाई भी उल्लेखनीय रही। अब, इसका ध्यान तपेदिक उन्मूलन पर है।

वर्ष 2000 से नए संक्रमणों के उत्पन्न और उत्पन्न संक्रमण—जैसे कि सार्स, बंद पड़, एम्पईआरएस, इटाला, एम्पईआरएस और कोविड 19 के लिए उपचारों से एजेंसी का काम अधिक ध्यान खींच रहा है। एक वैश्वीकृत, एका-दूसरे से बहुत अधिक जुड़े हुए परस्पर निर्भरता वाले विश्व में, स्वास्थ्य सुरक्षा सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। डब्ल्यूएचओ से हटने का फैसला वैश्विक समुदाय के अलावा खुद अपने सदस्य बड़े दानदाता का खेले जाना एक गंभीर चरण है, यह भी ऐसे समय में जब अन्य देशों का योगदान पहले से ही कम होता जा रहा है। अमेरिका के बाद, अगला सबसे बड़ा दानदाता देश जर्मनी है, जिसका एजेंसी के वित्त पोषण में योगदान लगभग 3 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, डब्ल्यूएचओ को कुछ राष्ट्र-राजकीय दानदाताओं से मिलने वाले धन में काफी वृद्धि हुई है। बिल एंड मेरीला गेट्स फाउंडेशन इस सूची में सबसे

ऊपर है, उसके बाद नंबर आता है यूरोपियन आयोग और विश्व बैंक का। गेट्स फाउंडेशन पॉलियो उन्मूलन और टीकों जैसे क्षेत्रों में काम में मदद कर रहा है। यदि अमेरिका द्वारा वित्तीय मदद बंद करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिलने वाला राष्ट्रीय वित्त पोषण नहीं बढ़ता, तो इसकी निर्भरता गेट्स जैसे निजी दानदाताओं पर बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के स्वतंत्र कामकाज के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं होगी। आलोचकों का मानना ​​है कि निजी वित्त पोषण के साथ कुछ शर्तें जुटी होती हैं, जो बदलने में वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे को प्रभावित कर सकती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के कामकाज को और अधिक कुशल, प्रदर्शनी और उत्तरदायी बनाने के लिए इसमें सुधार की मांग करना ज़रूरी है। महामारी के मॉडल, भारत ने भी 2020 में जी-20 और विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन जैसे बहुमूर्तीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया था। भारत का सुझाव है कि डब्ल्यूएचओ को कोविड-19 जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड और मापदंड तैयार करने चाहिए। अन्य देशों ने भी इसी रास्ता अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र नियामक होने के नाते, डब्ल्यूएचओ आलोचना के लिए खुला है और सुधारों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए मंच मौजूद है, लेकिन इसे मंग करना यह इस कदम से बलित करना सामान्य नहीं है। वहीं सुधार संबंधी काम का जवाब देते हुए, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसने अपने इतिहास में सुधारों का सबसे बड़ा सेट लागू किया है, जिसमें 'जवाबदेही, लागत-प्रभावीता और देशों में प्रभाव' शामिल हैं।—लेखक विज्ञान संबंधी विषयों के माहिर हैं।

संकीर्ण मानसिकता के लोग



— निर्मल रानी—

जिस समय अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन प्रथममंत्री नरेंद्र मोदी द्वारागत वर्ष 14 फरवरी 2024 को किया गया था उस समय भारतीय मीडिया में इसकी जोरदार चर्चा हुई थी। अबू धाबी में 27 एकड़ जमीन पर बने इस पहले कागण अरब जगत के कई देश 6 एव विशाल हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में 42 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस मंदिर के निर्माण हेतु 13.5 एकड़ जमीन अबू धाबी के कामकाज प्रिंस शेख मोहम्मद ने वर्ष 2015 में बीएपीएस संस्था को दान स्वरूप दी थी। गौरतलब है कि संयुक्त अरब इमीरात में लगभग 28 लाख भारतीय रहते हैं जो वहां की कुल जनसंख्या का लगभग 30: हिस्सा है। इससे पहले दुर्घट में मगान शिव व भगवान गणेश को दर्शन के लिए आया और वहां पर अंग अंग मंदिर और एक गुरुद्वारा तथा अबू धाबी में एक चर्च पहले से मौजूद थे परन्तु वहां कोई मंदिर नहीं था। हालांकि अबू धाबी में निर्मित हुए इस विराट व भव्य मंदिर के निर्माण के बाद यह प्रचारित करने की कोशिश की गयी कि यह अरब जगत में निर्मित पहला हिंदू मंदिर है परन्तु यह सच्चाई से कोसों दूर गोदी मीडिया द्वारा सजा की चापलूसी के लिये नया एक एव नटवटिभ नाथ था। क्योंकि बहरीन की राजधानी नमामा में निर्मित हिंदू समुदाय का श्रीनाथजी का मंदिर एक सदी से भी अधिक पुराना है। पड़ोसी देश संजुदी अरब में रहने और काम करने वाले हिंदू भी पवित्र अवसरों पर इस मंदिर में पूजा-पाठ करने आते हैं। ओमान की राजधानी मस्कट में 125 वर्ष प्राचीन मोतीश्वर मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है। जबकि मस्कट के ही रसूल में 150 साल पुराना कृष्ण-विष्णु मंदिर भी है। इस मंदिर को ओमान के सुल्तान ने ओमान में वित्त निगता के लिए समुदाय के लिए निगता के प्रतीक के रूप में निर्मित कराया था। इसके अलावा भी दुर्घट में संभन भारतीय समुदाय में दक्षिण भारतीयों के अलावा सिंधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और करीब सभी प्रमुख धर्मों के कई दशकों पुराने अनेक धार्मिक स्थान हैं। वहीं हिंदू मंदिरों में ही गीता अर्चना,हवन यज्ञ धर्म व आ पूजा करने के लिये कुमाराह, उत्सव व अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दुर्घट

और उसके आसपास के कुछ शहरों और खाड़ी के अन्य हिस्से में दिवाली की रात ठीक उसी तरह की रोशन होती है, जैसे भारत में होती है।

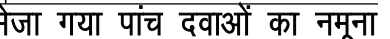
यह तो उन इस्लामिक देशों में मंदिरों की स्थिति है जहां मूलतः पूजा प्रतिबंधित नहीं जाती है परन्तु केवल धार्मिक सौहार्द व सम्मान के कारण अरब जगत के कई देश 6 धार्मिक संहिष्णुता का परिचय देते हुये एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं व परंपराओं का आदर व सत्कार करते हैं। निश्चित रूप से जब भारतीय समाज ऐसे ही खराब से बाखबर होता है। यदि हम अरब देशों में मंदिरों के निर्माण पर खुश हो सकें हैं। जब हम बांलादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे देशों में मंदिर गुरुद्वारा व चर्चो पर होने वाले हमलों पर क्रोधित होते हैं तो हमें क्यों सोचिएं की जिसाल पैरा कर दुनिया के सामने संहिष्णुता व सद्भावना का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। परन्तु यहाँ तो सत्ता के संरक्षण में धर्म के प्रति अतिशय कुल और ही होती जा रही है। गुजरात से शुरू हुआ धार्मिक अहिंसावादी का यह धिनासी खेल अब उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश,हरियाणा,राजस्थान,उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों तक जा पहुंचा है। कहीं महरिद्वार में नमाज अदा करने से रोका जा रहा है तो कहीं अरब देशों में ही नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गयी है। खुने के लिए गुदुआय जैसे बड़े शहर में पाकों या खुले स्थानों पर शांतिपूर्ण नमाज पढ़ने वालों का कई बड़े विरोध हो चुका है। हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में चर्चो पर भी हमने हत हारें हैं। महरिद्वारों के इन्सानों की हत्याएं व उनपर हमले होते रहते हैं। कहीं महरिद्वार पर भगवा फहराया जाता है तो कहीं पिर फकीरों की मजदूरी या दरवाजों का हिंसा व उपद्रव का निशाना बनाया जाता है। आता हमारे देश में ऐतिहासिक प्रभुशक्ति के साथ ऐसे सैकड़ों गुरु मस्जिद धर्मस्थान मिल जायेंगे जिसके लिये मुस्लिमों द्वारा जमीन दान में दी गयी है। आज खुले आम तो हमारे देश में सूफी फकीरों से जुड़े अनेक आस्तानों का संचालन गुरु मुस्लिमों द्वारा पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ किया जा रहा है।

कार्य बहिष्कार का अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, मांगा न्याय



के हथियारों को शीघ्र गिरफ्तारी करते हुए इस मुकदमें की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। अधिवक्ताओं ने एक स्वर से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की, ताकि अधिवक्ताओं का हित संरक्षित रह सके। इस बैठक के बाद पूरे दिन न्यायिक कार्य में सहयोग न करने का निर्णय लिया गया और अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

अध्यक्ष करुणाकर पात त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक व प्रदर्शन में महाराष्ट्र में कुमार सिंह, पूर्व मंत्री रामराज चौधरी, पूर्व अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष इद्रासन सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव, मधुसूदन पटेल, कृष्णराव पांडेय, प्रमोद कुमार त्रिपाठी, मूर्ति नारायण त्रिपाठी, अभिजीत सिंह, अभिषेक यादव, अमय मौर्या, अरविनाथ कुमार, रामकिशोर पटेल, सौरभ पटेल, दिनेश गुप्ता सहित तमाम अधिवक्ता शामिल रहे।

[illegible]

1 दवाएं मिली हैं। पांच दवाओं का नमूना लेकर जांच के लिए भेज गया है। अगर यह नमूने फेल होंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि दवाओं की जांच के लिए सरकारी अस्पतालों में अभियान के तहत आगे भी जांच की जाएगी। जिला अस्पतालों के साथ-साथ सभी सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता व मानक की जांच की जाएगी।

ड्रग वेयर हाउस के जरिए जिला के सरकारी अस्पताल में जीवन श्वक दवाएं भेजी जाती हैं। कारपोरेशन के द्वारा भेजी जाने वाली दवाओं का सैंपल लेकर जांच कराने का अधिकारी औषधि विभाग को है। इसी क्रम में यह जांच बुधवार को की गई है। जिला अस्पताल में 266 तरीके की दवाएं स्टोर में उपलब्ध होनी चाहिए। इसकी भी जांच की गई है। संयुक्त जिला अस्पताल के इस दवा स्टोर रूम में जांच के दौरान प्रथम दृष्टया कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। अब जिन दवाओं को सैंपल लिया

मन शान्तिमान रहे । पढाकाश में ज्ञान का जौरी



पौष्टिक आहार किट का वितरण किया गया। जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अधीक्षक डा. अमनीश कुमार तिवारी ने कहा कि टीबी मरीजों को कम से कम दो माह तक मास्क पहनना जरूरी होता है। टीबी की जांच के लिए अस्पताल आने एवं नियमित दवा के सेवन करने की जरूरत होती है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित समुदायस्वास्थ्य कर्मी को टीबी मक भारत बनाने में सहयोग

करने की अपील की गई। सीएचसी अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। सरकार की ओर से टीबी मरीजों को निःशुल्क जांच, दवा और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

त अभियान के

[illegible]

सांवादना-देवीगीत। साहसिक
में स्नान कर बेटी के साथ कलौ रही
एक युवा की स्नान स्थल रक्षार्थ स्तंभ पर
हार्दिकता से नितो हो गयी। सुमना
पिलान पर कुमन लेकी कछुदी पल
तिलान स्वाध्याय कर्मियो ने उत्कच
वेकचय कर एनुवत्त के जरिउ
महोदी देवराध था मडिक्ल कालेज
भजयाय। गोरखपुर प जिला
के बडलखण थाना हो के स्नान घाट
की रहने लगी चन्द्रनाती बेटी (70)
पली धनी प्रासाद पुत्र अपने बेटी के
साथ प्रायगर्जना साहसिक में स्नान
करने गयी थी। स्नान करने के बाद
वह स्नान के घर लौट रही थी,जैसे ही
वह देवीराध स्थल रवेने स्तंभ पर
पहुंची तिलान होकर हार्दिकता आ गया
और वह अवेत होकर जमीन पर गिर
पडी। इसकी जानकारी होते ही स्नान
स्थल रक्षार्थ पर कुमन लेकी कछुदी
पर तिलान की। जमाना अवेत सिद्धी
व डी.आनाना साथ स्वाध्याय कर्मियो
के साथ युवा को पुनः उत्तरी वेकचय
कर गूढा के एनुवत्त के जरिउ
महोदी देवराध था मडिक्ल कालेज
भजयाय। शांति चिकित्सालय में मृग घोषि

